

“ मुख्य समाचार ”

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा— जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाएगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लगाया आरोप।
- मुख्यमंत्री ने कहा— एच.आर.टी.सी. की बसों को पंजाब में रोककर उसमें पोस्टर लगाने के संदर्भ में पंजाब सरकार से होगी बात।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में फिन्ना सिंह बहुद्देशीय परियोजना का किया गया शामिल।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों खासकर जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाएगी। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह नीति जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होगी ताकि किसी भी विभाग, निगम या बोर्ड में कोई पद खाली न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युक्तिकरण की नीति पर काम कर रही है। इससे पूर्व विधायक डॉ. जनकराज के मूल सवाल का जवाब देते हुए बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी चिंता का विषय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जनजातीय क्षेत्रों में खाली पदों की समस्या को दूर करने के लिए ट्राइबल सब कॉर्डर फिर से आरंभ करने पर विचार करने का आग्रह किया। विधायक राकेश जमवाल के एक सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार बंदोबस्त का काम तेज करने के लिए प्रयासरत है ताकि इस कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बंदोबस्त का कार्य तेज करने के लिए सरकार ने आधुनिक मशीनों का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन अभी तक यह मशीनें आनी बाकी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक दलीप ठाकुर के एक सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार को बीते वर्ष जलजीवन मिशन के तहत 9 सौ 25 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अभी तक एक सौ 37 करोड़ रुपए ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि विभाग इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय से लगातार पत्राचार कर रहा है ताकि इस राशि को हासिल किया जा सके। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के एक सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानी विभाग ने इटली की एक कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसके तहत कुल्लू ज़िले के बजौरा में सेब के 50 हजार रूट स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल दिसंबर में बागवानों को ये पौधे 4 सौ 50 रुपये में उपलब्ध करवाए जाएंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023–24 में प्रदेश में आ रहे बिना क्वारंटीन के सेब के पौधों के खिलाफ मुहिम चलाकर 25 वाहन जब्त किए और इनमें 2 लाख 95 हजार 7 सौ 25 पौधे नष्ट किए गए। इसी तरह 2024–25 में बिना क्वारंटीन के लाए जा रहे 68 हजार पौधों को नष्ट किया गया है।

बागवानी मंत्री ने माना कि प्रदेश में सेब के पौधों का रूट स्टॉक एक अरसे से तैयार नहीं हो पा रहा है।

बजट चर्चा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। विधानसभा में आज राज्य के वर्ष 2025-26 के आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार महज दो साल के शासनकाल में 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण ले चुकी है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में केवल 28 हजार 7 सौ 44 करोड़ का ही ऋण लिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर केंद्रीय योजनाओं के पैसे से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन देने का भी आरोप लगाया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता.....

डिस्पैच- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में वर्ष 2025-26 के राज्य बजट पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ बढ़ गया है। जयराम ठाकुर ने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने कभी कर्ज लेने की सीमा का उल्लंघन नहीं किया लेकिन सुक्खू सरकार ने बीते दो वर्षों में इस सीमा को पार किया है। उन्होंने मौजूदा बजट को हिमाचल के इतिहास में सबसे कम ग्रोथ वाला बजट बताया और इसे दिशाहीन करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की वित्तीय नीतियों के साथ प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और प्रदेश के हित में निर्णय लें। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष के दावों का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाली आरडीजी में कमी के कारण राज्य के बजट का आकार प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल को केवल 3 हजार 2 सौ 57 करोड़ रुपए आरडीजी मिलेगी, जबकि भाजपा सरकार के समय जीएसटी मुआवजे के तहत राज्य को 16 हजार करोड़ मिले थे। सुक्खू ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में देश की कर्ज लेने की सीमा पहले साढ़े चार प्रतिशत फिर साढ़े तीन प्रतिशत थी लेकिन केंद्र सरकार ने इसे घटाकर अब तीन प्रतिशत कर दिया है। चर्चा में विधायक आशीष बुटेल, हंसराज, इन्द्र सिंह गांधी, भवानी सिंह पठानिया, रीना कश्यप और राम कुमार ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री वक्तव्य

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि एच.आर.टी.सी. बसों को पंजाब में रोककर उसमें भिंडरेवाला के पोस्टर लगाने के संदर्भ में वे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने यह बात विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा उठाए गए मामले के उत्तर में दी। मुख्यमंत्री ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलीबारी किए जाने की घटना के संदर्भ में वक्तव्य देते हुए कहा कि इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलीबारी की घटना में कुल 4 शूटर शामिल थे। इस घटना में हरियाणा के रोहतक के 2 शूटरों की पहचान हो चुकी है और इनकी धरपकड़ के लिए अलग-अलग टीमों गठित कर पड़ोसी जिलों व राज्यों

को भेजी गई है। इसमें हरियाणा पुलिस की भी सहायता ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह, व डी.आई.जी. मंडी सौम्या सांबशिवन की अध्यक्षता में एस.आई.टी. का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के बारे में भी सदन को अवगत करवाया।

जयराम ठाकुर

इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब जाने वाली एच.आर.टी.सी की बसों में भिडरावाले के झंडे लगाए जा रहे हैं, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत अगस्त 2024 में हिमाचल प्रदेश की फिन्ना सिंह बहुद्देशीय परियोजना को शामिल किया गया है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में संसद में उन्होंने ये जानकारी दी। राजभूषण चौधरी ने बताया कि इस परियोजना में ब्यास नदी में चक्की खड्ड पर एक बांध परिकल्पित है, जिसे कलाम नाला के साथ एक किलोमीटर से अधिक लंबाई के लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य कांगड़ा जिले में 8 हजार 4 सौ 43 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई और एक दशमलव 8-8 मैगावॉट की जलविद्युत उत्पादन क्षमता मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में फिन्ना सिंह परियोजना के लिए 67 करोड़ 5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता के लिए मुख्य स्वीकृति जारी की गई है। राजभूषण चौधरी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुसूची के अनुसार इस परियोजना को मार्च 2026 तक पूरा किया जाना है।

“ मुख्य समाचार एक बार फिर ”

- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा— जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाएगी सरकार।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कर्ज लेने के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लगाया आरोप।
- मुख्यमंत्री ने कहा— एच.आर.टी.सी. की बसों को पंजाब में रोककर उसमें पोस्टर लगाने के संदर्भ में पंजाब सरकार से होगी बात।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में फिन्ना सिंह बहुद्देशीय परियोजना का किया गया शामिल।
